

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 30, शुक्रवार, शाके 1942-अगस्त 21, 2020 <i>Sravana 30, Friday, Saka 1942-August 21, 2020</i>	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2020

संख्या एफ. 13(21)विशा/विस/2020 :-राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020 जैसा कि दिनांक 21 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2020 का विधेयक सं.21

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 13 मई, 2020 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3-ख का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की विद्यमान धारा 3-ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"3-ख. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए और प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के लिए अधिभार.- (1) अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य समस्त लिखतें ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगी, जो ऐसी लिखतों पर इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए या सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित की जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार धारा 3 के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क और धारा 3-क के अधीन प्रभार्य किसी अधिभार के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।

(4) उप-धारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए, और उस व्यक्ति के, जिसके माध्यम से अधिभार संगृहीत किया जाता है, कर्तव्यों और पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(5) इस धारा के अधीन संगृहीत अधिभार का उपयोग गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए या सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कोविड-19 के आकस्मिक प्रकोप से पीड़ित जनता को खाद्य, आश्रय, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में तुरन्त राहत उपलब्ध करवाने के लिए और आकस्मिक स्थितियों जैसे सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि के लिए संसाधनों की भावी आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 3-ख के विस्तार को व्यापक किया जाना समुचित समझा गया है। इसलिए यह प्रस्तावित है कि धारा 3-ख के अधीन संगृहीत अधिभार, जो कि गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, का उपयोग सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनों के लिए भी किया जायेगा। तदनुसार, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3-ख को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 13 मई, 2020 को राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 4) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 14 मई, 2020 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

**अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।**

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को धारा 3-ख के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए और उस व्यक्ति के, जिसके माध्यम से अधिभार संगृहीत किया जाता है, कर्तव्यों और पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषय से संबंधित है।

अशोक गहलोत,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No.21 of 2020**(Authorised English Translation)****THE RAJASTHAN STAMP (AMENDMENT) BILL, 2020****(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)***A**Bill**further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 13th May, 2020.

2. Amendment of section 3-B, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 3-B of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the following shall be substituted, namely:-

"3-B. Surcharge for conservation and propagation of cow and its progeny and for mitigating natural or man-made calamities.- (1) All instruments chargeable with duty under section 3 read with Schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 20 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny, or for the purposes of mitigating natural or man-made calamities like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire etc.

(2) The surcharge chargeable under sub-section (1) shall be in addition to any duty chargeable under section 3 and any surcharge chargeable under section 3-A.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (1), provisions of this Act shall, so far as may be, apply in relation to the surcharge, chargeable under sub-section (1) as they apply in relation to the duty chargeable under section 3.

(4) Save as provided in sub-section (3), the State Government may make rules for collection of surcharge leviable under this section and for regulating the duties and remuneration of the person through whom surcharge is collected.

(5) The surcharge collected under this section shall be utilized for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny, or for the purposes of mitigating natural or man-made calamities like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire etc."

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Stamp (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 4 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to provide immediate relief to people suffering from the sudden outbreak of COVID-19 in the form of food, shelter, transportation and health services and also having in mind the future need of resources for emergent situations like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire etc., it is considered appropriate to widen the scope of section 3-B of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999). Therefore, it is proposed that the surcharge collected under section 3-B which is utilized for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny, shall also be utilized for the purposes of mitigating natural or man-made calamities like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire etc. Accordingly, section 3-B of the Rajasthan Stamp Act, 1998 is proposed to be amended.

Since the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Stamp (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 4 of 2020), on 13th May, 2020, which was published in Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV(B), dated 14th May, 2020.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules for collection of surcharge leviable under section 3-B and for regulating the duties and remuneration of the person through whom surcharge is collected.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.